(ख) राज्य सरकार द्वारा भूमि प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

जल-मूतल परिवहन मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन): (क) और (ख) इलाहाबाद में यमुना नदी का प्रस्तावित पुल राष्ट्रीय राजमार्ग पर नहीं आता है । राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ उपयुक्त शहरी सम्पर्क के रूप में परियोजना को शुरू करने के लिए नवम्बर, 1986 में सिद्धान्त रूप से सहमति दी गई थी बशर्ते कि राज्य सरकार कुल परियोजना लागत का $\frac{1}{3}$ हिस्सा वहन करे तथा अपनी लागत से ही भूमि अधिग्रहण करे । उत्तर प्रदेश सरकार ने न तो भूमि प्राप्त की है और न ही परियोजना लागत का $\frac{1}{3}$ हिस्सा वहन करने का वचन दिया है। फिर भी पुल के निर्माण के लिये विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है ।

Functioning of telecommunications and telephones system

232. SHRI B. SArYANARAYAN REDDY: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Governmeni have taken any steps to set right the deteriorating functions of telecommunications and telephones system in the country; and

(b) if so, whatare the details thereof ?

THE MINISTER OF SURFACE TRANSPORT AND THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI K. P. UNNIKRISHNAN): (a) and (b) The telecommunication services have not been deteriorating. Continuous watch is kept on the performance and operation, which is monitoted locally as well as ,. centrally.

To improve the operation and maintenance of Ihe services further the following steps are being taken by the Department on a regular basis:

(i) Replacement of worn-out electro-mechanical exchanges by electronic ones;

(ii) Replacement of worn-out telephone instruments by new ones;

(iii) Replacement of fault-prone cables;

(iv) Replacement of heavy overhead alignmeits by underground cables;

(v) Provision of cable ducts in. large cities;

(vi) Provision of more public telephones;

(vii) Customer-oriented training to the staff of the Department;

(viii) Modernisation of telegraph network by installing electronic store-forward message switching systems, electronic teleprinters, electronic key board and other related devices |

(ix) Providing mopeds to "telegraph messangers for expediting delivery of telegrams in far flung areas.

दूरभाष सलाहकार समितियों के गठन में विलंब

233. श्री विश्वासराव रामराव पाटिल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की दूरभाष सलाहकार समितियों का कार्यकाल समाप्त हो गया है और इन शहरों की दूरभाष सलाहकार समितियों का गठन अभी तक नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) विलंब के क्या कारण हैं ?

जल-मूतल परिवहन मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) सलाहकार समिति के गठन सम्बन्धी नीति की समीक्षा की जा रही है । नीति को अंतिम रूप दिए जाने के बाद इन समितियों का गठन किया जायेगा ।

Yoga classes in foreign countries

234. SHRJ KAILASH PATI MISHRA: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) the country-wise number of persons abroad who attend Yoga classes being helped by the Indian Embassies;

(b) what is the number of Yoga teachers so engaged and how many more are proposed to be sent abroad for the said proposed classes; and

(c) whether there are requests from more countries for such classes; if so, what are their names and what steps are being taken to meet their requests ?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI I. K. GUJRAL): (a)

Moscow (USSR).. 150 persons

Suva (Fiji).... 30 persons;

(b) One teacher each in Moscow and Suva. A second Yoga teacher is proposed to be deployed in Moscow.

दूरदर्शन और आकाशवाणी को स्वायत्तता

235. डा० रत्नाकर पाण्डेय :
श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी :
श्री कपिल वर्मा :
श्रीमती वीणा वर्मा :
श्री पशुपतिनाथ सुकुल :
श्रीमती सुधा विजय जोशी :
श्री बैकुंठनाथ साहू :
श्रीमती सूर्यकांता जयवंतराव पाटिल :
श्री सत्यप्रकाश मालवीय :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन और आकाशवाणी को स्वायत्तता प्रदान करने के लिए प्रस्तावित योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) और (ख) स्वायत्त प्रसारण निगम बनाने से संबंधित विधेयक संसद के इसी सत्र में प्रस्तुत किया जा रहा है ।